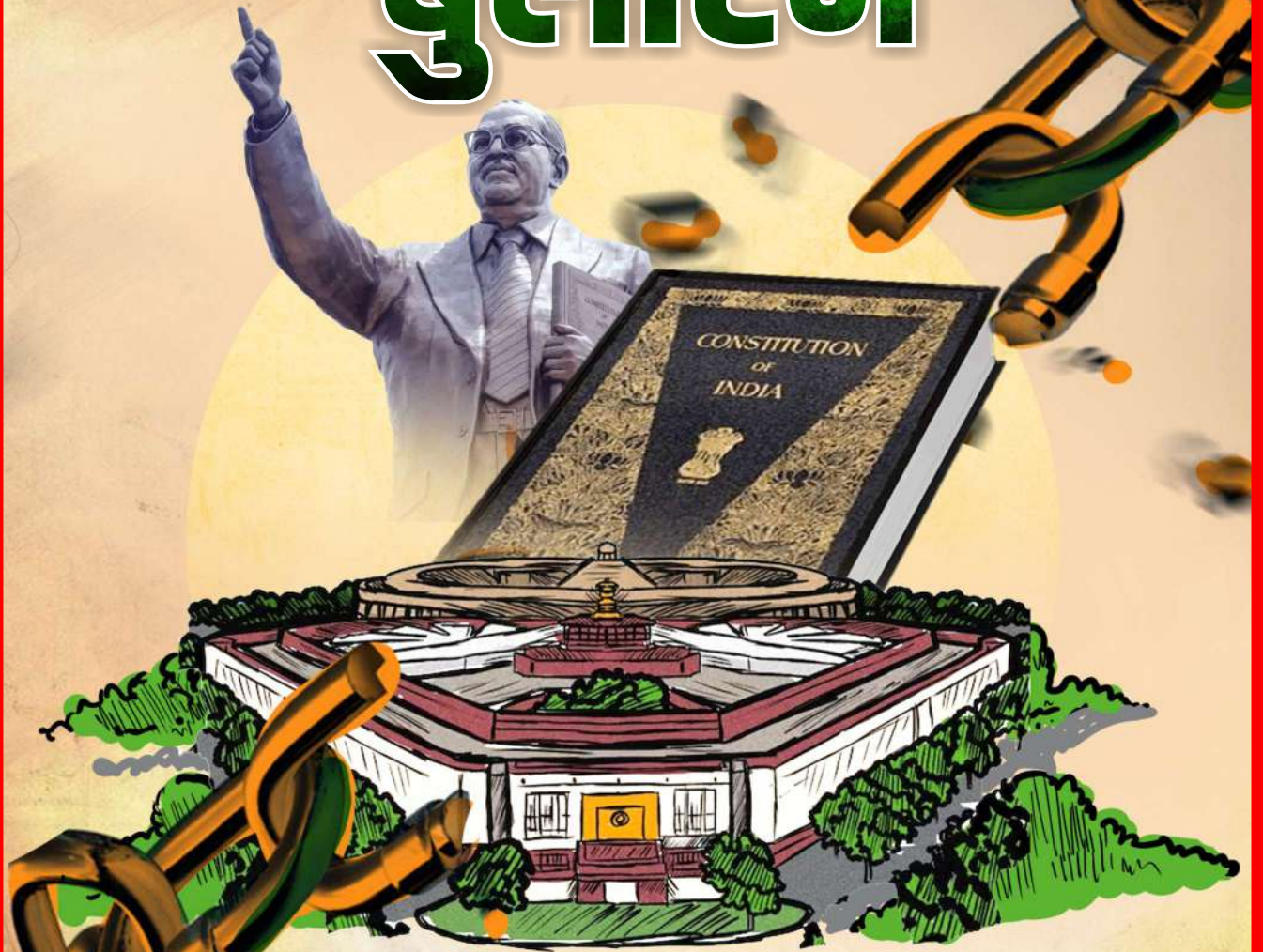


समाजवादी बुलेटिन



भाजपा हटाओ
संविधान बचाओ

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है। सपा के पास मजबूत संगठन है। पार्टी के युवा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करें। समाजवादी नीतियों से ही सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

मुलायम सिंह यादव

संस्थापक, समाजवादी पार्टी



प्रिय पाठकों

आप सभी के प्यार,
उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन
से आपकी प्रिय पत्रिका
समाजवादी बुलेटिन,
बदली हुई साज-सज्जा के
साथ अपने तीसरे वर्ष में
प्रवेश कर चुकी है। हम
आपके आभारी हैं कि अभी
तक के सफर में हम
आपकी कसौटी पर खरे
उतर सके हैं। हम भरोसा
दिलाते हैं कि भविष्य में
भी आपकी उम्मीदों पर
खरा उतरने की हम कोई
कसर नहीं छोड़ेंगे। कृपया
अपना प्यार यूँ ही बनाए
रखें।

धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

✉ samajwadibulletin19@gmail.com

✉ bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

🌐 /samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97



उत्तर से दक्षिण तक जातीय जनगणना की गूंज

34

08 कवर स्टोरी

भाजपा हटाओ संविधान बचाओ



सपा ने सदन में सरकार को घेरा

06



उत्तर प्रदेश विधानमंडल के हाल में संपन्न संक्षिप्त सत्र में समाजवादी पार्टी ने जनहित के तमाम मुद्दों पर भाजपा सरकार को विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की खराब होती स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार से जवाब मांगा मगर सरकार की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी ने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षकों के साथ होते अन्याय व लगातार धरना दिए जाने पर विधानसभा में चिंता जाहिर की।

यूपी में आधी आबादी सर्वाधिक असुरक्षित

38

खंजर से पूछते हो कि क्रांतिल किधर गए?

04

खंजर से पूछते हो कि क़ातिल किधर गए?



उदय प्रताप सिंह



सं

सद पर हमला देश के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर शंका जाहिर की जा रही थी की 21 साल बाद 13 दिसंबर को संसद पर फिर हमला हो सकता है। हमारी सिक्योरिटी और जासूसी

एजेंसियों ने निश्चित रूप से इस खबर के बाद कुछ सुरक्षा के ज़रूरी कदम उठाए होंगे फिर ऐसी घटना कैसे हो गई?

प्रश्न यह है कि यह चार हमलावर जो कि युवा हैं और देश के अलग-अलग राज्यों से संबंधित हैं, वे इस एक साजिश में शामिल कैसे हुए और किसने किए? सरकारी पार्टियों के एक सांसद की सिफारिश पर इनको संसद में प्रवेश करने की अनुमति पत्र मिला। संसद में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों उपस्थित नहीं थे, ये अच्छी बात थी।

ऐसी तारीख को भाजपा के सांसद द्वारा जारी किए गए पास पर चार युवा हमलावरों को विभिन्न राज्यों से होने के बावजूद संसद में प्रवेश भी मिल गया। यह सब संयोग हो सकता है लेकिन संयोग है कि साजिश है, इसकी जांच पड़ताल गंभीरता से किसी विश्वसनीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

वे देशद्रोही नहीं थे, वे वंदे मातरम का भी नारा लगा रहे थे और नहीं चलेगी भी कहते थे

और गनीमत है कि सब के सब हिंदू थे अन्यथा यह देश इस समय एक अभूतपूर्व तनाव से गुज़र रहा होता। हमलावर व्यवस्था के खिलाफ भी बोल रहे थे।

न्याय प्रक्रिया में एक शब्द होता है सरकमस्टेंशियल एविडेंस यानी स्थितिजन्य गवाही। अगर इस पर भरोसा किया जाए तो यह नियोजित साजिश थी जिसमें किसी बड़े नेता या नौकरशाह या किसी जिम्मेदार व्यक्ति का हाथ हो सकता है यह पड़ताल का विषय है अन्यथा इतनी कड़ी सुरक्षा के कई घेरे पार करके संसद में पहुंचना किसी के लिये आसान काम नहीं है।

बहरहाल यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है इसलिए इसपर हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस सांसद की सिफारिश पर इन हमलावरों को संसद में प्रवेश मिला उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उससे प्रश्न किया जाना चाहिए कि चार

विभिन्न राज्यों के हमलावरों को प्रवेश की सिफारिश करना महज़ संयोग है या साजिश है। क्या आप उन चारों से परिचित थे?

हालांकि चुनाव के पहले ऐसे काम पहले भी होते आए हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मान और संविधान की रक्षा के हित में हम सबको इस विषय पर एक देशभक्त भारतीय के रूप में सोचना चाहिए।

जय हिंद



समाजवादी पार्टी ने सदन में सरकार को घेरा



बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के हाल में संपन्न संक्षिप्त सत्र में समाजवादी पार्टी ने जनहित के तमाम मुद्दों पर भाजपा सरकार को विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की खराब होती स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार से जवाब मांगा मगर सरकार की

ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी ने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षकों के साथ होते अन्याय व लगातार धरना दिए जाने पर विधानसभा में चिंता जाहिर की।

28 नवंबर से शुरू हुए चार दिन के सत्र में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के

छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में शून्य शुल्क प्रवेश प्रणाली के प्रावधान को खत्म कर उनके हितों को नुकसान पहुंचाने पर सदन से वाकआऊट भी किया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में सिर्फ चार दिन के सत्र और विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने की

आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार जनता के सवाल उठाने पर रोक लगाना चाहती है। विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार पिछले बजट की धनराशि ही खर्च नहीं कर पा रही है तो फिर अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत थी? यह खोखला बजट है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह अजीब बात है कि समाजवादी पार्टी सन् 2017 से सरकार से बाहर है। जवाब उनको देना चाहिए जो सत्ता में हैं पर आज भी यह सवाल समाजवादी पार्टी से ही कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है चाहे वह जिला अस्पताल हो या पीएचसी या सीएचसी हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो। सरकार जानबूझकर सरकारी अस्पतालों को खत्म कर रही है ताकि प्राइवेट नर्सिंग होम को बढ़ावा मिले। प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट लोगों से सरकार मिली हुई है। सूचनाएं मिल रही हैं कि सरकार सीधे-सीधे प्राइवेट लोगों की मदद करना चाहती है। सरकार प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहती है।

श्री यादव ने कहा कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। भाजपा के एक पूर्व सांसद अपने पौत को पीजीआई में इलाज के लिए लाए थे। पीजीआई में उन्हें इलाज नहीं मिला और वह उसे नहीं बचा पाए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र में हम सब लोग जनता के लिए जवाबदेह हैं। ऐसे में भाजपा के पास जवाब नहीं होता है। तब वह निजी टिप्पणी पर आ जाते हैं। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं ताकि जनता की जवाबदेही से बचा जा सके।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की



आवाज दबाने के लिए नए-नए कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। यह तानाशाही रवैये का परिचायक है। उन्होंने कहा कि भाजपा का इरादा लोकतंत्र को कमजोर करने का है। विधानसभा का सत्र बहुत कम दिनों का आहूत होता है। सदन में चर्चा होगी तभी तो विकास होगा। श्री यादव ने कहा कि भाजपा राज में सब तरफ बर्बादी है। अस्पताल जर्जर है। चिकित्सा सेवा पूरी तरह से बर्बाद है। पढ़ाई-चौपट है। प्राइमरी स्कूलों में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो काम मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। गन्ना के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, धान नहीं खरीदा जा रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूंजीनिवेश के बड़े-बड़े दावे किए लेकिन जमीन पर कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। न उद्योग लगे न रोजगार मिला। सड़कों को गड़बड़मुक्त करने के नाम पर बजट तो लुट गया पर गड्डे नहीं भरे गए। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।

श्री यादव ने कहा कि देश के बहुत सारे दल

जातीय जनगणना के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। सबको बराबर का हक और सम्मान मिले इसके लिए आरक्षण आवश्यक है लेकिन भाजपा निजीकरण को बढ़ाकर आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में अनियमितता के चलते शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलित हैं। भाजपा सरकार उनकी समस्या के समाधान के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता की दिक्कतें और कठिनाइयों का समाधान भाजपा सरकार की विदाई से ही संभव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में परेशान जनता भाजपा को सत्ता से बाहर अवश्य करेगी।

भाजपा हटाओ संविधान बचाओ

बुलेटिन ब्यूरो

भाजपा के राज में संविधान-लोकतंत्र को बचाये रखना बड़ी चुनौती है और समाजवादी पार्टी लगातार इसके लिए मुहिम चलाए हुए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए संविधान की रक्षा का संकल्प ले रखा है और इसके लिए वह लगातार मुखर रहे हैं। संसद में 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन ने अपनी चौथी बैठक में 22 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन का फैसला लिया तो यूपी में समाजवादी पार्टी के

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से व्यापक स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने का निर्देश दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इस प्रदर्शन को कामयाब बना दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 22 दिसंबर को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा





सरकार का विरोध किया। प्रदर्शन के केंद्र में संसद सत्र में भाजपा सरकार द्वारा 146 सांसदों का अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया निलंबन था। धरना प्रदर्शन का उद्देश्य लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने के लिए भाजपा सरकार को हटाना रहा। समाजवादी पार्टी के इस धरना-प्रदर्शन में जिलों में आमजन भी स्वतः स्फूर्त पहुंच गए जिससे समाजवादी साथियों के हौसले बढ़ गए।

धरना प्रदर्शन में नेताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाजपा सरकार की किसान, नौजवान, गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया। सभी जिलों में यह धरना-प्रदर्शन किया गया।

धरना-प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रही है। भाजपा आम जनता के संवैधानिक अधिकार खत्म कर तानाशाही कर रही है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हरायेगी।

समाजवादी पार्टी लगातार यह कहती रही है कि भाजपा सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी काफी पहले से मुहिम भी चला रही है। विपक्षी

सांसदों के इतनी बड़ी संख्या में निलंबन के बाद अब पूरा देश यह मानने लगा है कि भाजपा सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है जिससे संविधान भी खतरे में है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और संविधान के अनुसार देश को चलाने की न केवल पैरोकारी करती रही है बल्कि उसपर अमल भी करती है पर हाल के दिनों में जिस तरह भाजपा सरकार में लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम हुआ है, उससे सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है।

भाजपा सरकार ने कई ऐसे नीतिगत फैसले लिए जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ा। विपक्ष

भाजपा का बर्ताव असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष के प्रति भाजपा नेतृत्व का विद्वेषपूर्ण रवैया पूर्णतया असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा ने विपक्ष की हर आवाज को कुचलने का इरादा कर लिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उसे न विश्वास है और न ही संविधान पर उसकी निष्ठा है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान के दुरुपयोग और एकाधिकारी प्रवृत्ति के प्रति संदेह जताया था। उनका अंदेशा सही साबित होने जा रहा है।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा राज में अघोषित तानाशाही की प्रवृत्तियां साफ नज़र आ रही है।

अच्छा हो, सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले जिससे मंत्रीगण और सत्तापक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोकहित के

कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वह आधार सत्तापक्ष पर लागू हो तो शायद उनका एक दो सांसद, विधायक ही बचेगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने विरोधियों की सदस्यता छीनने के कुचक्र के साथ उनको बदनाम करने के लिए सरकारी एजेंसियों, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई आदि का इस्तेमाल करके इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी नष्ट कर रही है। लोकतंत्र में ऐसी हरकतों का कोई स्थान नहीं हो सकता है। 🇮🇳







की आवाज दबाने में संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। सरकार की नोटबंदी से कोई फायदा नजर नहीं आया जबकि नोटबंदी के इस फैसले से देशवासी परेशान हुए, हलकान हुए। कड़ियों की जान गई। सरकार ने इसके तमाम फायदे गिनाए थे मगर अब यह स्पष्ट हो गया है कि इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और न ही आतंकवाद का खात्मा हो सका। तमाम उद्योगपति बैंकों का धन लेकर देश छोड़ गए मगर भाजपा सरकार उन्हें वापस नहीं ला सकी।

संविधान और लोकतंत्र के खतरे में होने की ताजा मिसाल विपक्ष के 146 सांसदों का निर्लम्बन है। आजादी के बाद से अब तक इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का संसद से निर्लम्बन पहली बार हुआ है। सांसदों का निर्लम्बन क्यों हुआ? क्या संसद में घुसपैठ की ताजा घटना पर गृहमंत्री से बयान देने की मांग अनुचित है? क्या सांसदों को अपने विचार प्रकट करने का हक नहीं है। अगर संसद की सुरक्षा को लेकर सांसद कोई मांग कर रहे हैं तो क्या उसे इस तरह अनसुना किया जा सकता है।

क्या यह अलोकतांत्रिक नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना असंवैधानिक कृत्य नहीं कहलाएगा? भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है और यह संविधान व लोकतंत्र से ही चलेगा।

INDIA की बैठक में एका का संकल्प



बुलेटिन ब्यूरो

INDIA गठबंधन की चौथी बैठक में शामिल हुए सभी 28 विपक्षी दलों ने एकजुटता का संकल्प लिया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें शीघ्र सीटों का तालमेल तय करना शामिल रहा।

इस बैठक में चर्चा हुई कि हर राज्य में जो बड़ी पार्टी हो, वही राज्य में गठबंधन का नेतृत्व करे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बैठक के बाद अपना यही मत व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव



शुरुआत से ही यह बात कहते रहे हैं कि जिस राज्य में जो दल भाजपा से मुकाबला कर रहा है उसे ही INDIA गठबंधन का नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वह ज्यादा बेहतर तरीके से भाजपा को हरा पाएगा।

अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने श्री अखिलेश यादव के विचार को आगे बढ़ाया है। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एकजुटता की वकालत करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और यूपी में 80 हराओ-लोकतंत्र

बचाओ के तहत हम सब जल्द ही चुनाव को लेकर जनता के बीच नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा 80 हारेगी और देश की सत्ता से बेदखल हो जाएगी।

19 दिसंबर को नई दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन में देशभर से 28 दल शामिल हुए और उन्होंने गठबंधन की मजबूती के लिए विचार विमर्श किया। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और तय हुआ कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग तय हो जानी चाहिए ताकि चुनाव की तैयारी के लिए वक्त मिल जाए। एकजुटता के लिहाज से यह बैठक काफी अहम रही। पहले तीन बैठकें पटना, बंगलुरु व मुंबई में हो चुकी हैं। चौथी बैठक दिल्ली में हुई और इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे आदि शामिल हुए।

बैठक में तय हुआ कि सीटों की शेयरिंग राज्यस्तर पर होगी और किसी राज्य में कोई दिक्रत होगी तो INDIA गठबंधन के प्रमुख नेता उसपर निर्णय लेंगे। बैठक में संसद से 146 सांसदों के निलंबन पर भी विमर्श हुआ और इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए इसके खिलाफ देशभर में आंदोलन करने का फैसला हुआ। बैठक में भाजपा सरकार की कुनीतियों से परेशान जनता की कठिनाइयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कार्यक्रम





बनाने पर विचार हुआ क्योंकि भाजपा राज में आम जनता इन मुद्दों से काफी परेशान है। गठबंधन की बैठक में ईवीएम पर भी चर्चा हुई और तय हुआ कि चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी कि वीवीपैट को ही बैलट पेपर समझा जाए। बैठक से पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने काफी देर तक चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव भी मौजूद थे।

संविधान तभी बचेगा जब भाजपा हारेगी



बुलेटिन ब्यूरो

का

नपुर देहात के
माती में
संविधान दिवस

पर 26 नवंबर को आयोजित संविधान बचाओ महारैली में संविधान-लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हराने का संकल्प लिया गया। महारैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री

अखिलेश यादव ने कहा कि देश में संविधान बचाने के लिए समाजवादी लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करने और जोखिम उठाने का काम कर रहे हैं। आज हम सभी लोग संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं। साथ ही हम संविधान देने वाले और जीने का अधिकार दिलाने वाले महान नेताओं बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, डॉ राममनोहर

लोहिया, नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं।

श्री यादव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। यह दिन हमें बताता है कि अगर लोकतंत्र जिन्दा रहेगा और संविधान बचा रहेगा तो हमें जो एक वोट का अधिकार मिला है उसके माध्यम से हम सरकारों से अपना अधिकार ले सकते हैं।



कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद राजाराम पाल द्वारा आयोजित महारैली को सम्बोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। भाजपा सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। थाने और तहसीलों में जमकर लूट हो रही है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा के लोग

बड़े-बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हैं। प्रदेश में भाजपा के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं। पूरे प्रदेश में जमीनों की हेराफेरी में सबसे ज्यादा भाजपा के लोग शामिल हैं। इस सरकार में नौकरियों में बड़े पैमाने पर हेरीफेरी हो रही है। पिछड़ों, दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। भाजपा पीडीए का हक छीन रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए ही भाजपा के एनडीए को हरायेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना कराकर सभी

जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से हक और सम्मान दिलाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठे हैं। उनकी हर बात झूठी है। भाजपा ने कहा था नौजवानों को नौकरी देंगे, नहीं दी। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। खाद नहीं मिल रही है। सरसों का तेल महंगा मिल रहा है। फसलों की कीमत नहीं मिल रही है। महंगाई चरम पर है। डीजल-पेट्रोल महंगा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हटाकर महंगाई बेरोजगारी हटाना है। महारैली में श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी विचारधारा के महापुरुषों सर्वश्री मनोहर लाल, हरमोहन सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, प्रभु दयाल, जसवंत सिंह, राधेश्याम, मथुरा पाल, योगेन्द्र पाल आदि को समाजवादी आंदोलन को मजबूती देने और ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनके योगदान को भी याद किया। महारैली में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए श्री अखिलेश यादव का स्वागत किया। महारैली के संयोजक पूर्व सांसद राजाराम पाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सभी लोग श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं।



संविधान बचाने को सपा से जुड़ रहा समाज का हर तबका

बुलेटिन ब्यूरो

फि

दिसंबर को पाल, बघेल, धनगर समाज की मंडलीय महापंचायत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बड़ी तादाद में आए समाज के लोगों को संबोधित करते हुए

रोजाबाद जनपद के टुंडला में 9

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश के लोग आज जातीय जनगणना के पक्ष में आ गए हैं।

यह माहौल इसलिए बना है क्योंकि मंडल कमीशन, संविधान की मूल भावना के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। संविधान की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। समाज का हर तबका संविधान रक्षा की मुहिम से जुड़ रहा है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि पाल, बघेल, धनगर समाज के हितों की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी ही, साथ ही आप सभी का इस लड़ाई में सहयोग भी चाहिए ताकि जाति के संख्याबल के आधार पर हक और सम्मान दिलाया जा सके।

श्री यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर को याद करें







जिन्होंने दलित और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देकर सम्मानित किया था। इसके बाद मंडल कमीशन ने हमारी पिछड़ी जातियों को अधिकार दिलाने का काम किया था। श्री यादव ने माता अहिल्याबाई होल्कर को नमन करते हुए कहा कि वे जितनी आप सबके लिए सम्माननीय हैं उससे ज्यादा हम लोगों के लिए सम्मानित हैं। हर वर्ग के लोग उनके योगदान को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादियों की सरकार बनने पर लखनऊ में गोमती रिवरफ्रंट पर उनकी सबसे शानदार प्रतिमा लगाने का काम किया जाएगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी पूरी होगी जब जातीय जनगणना होगी और लोगों को समानुपातिक हक मिलेगा। यह लड़ाई लंबी है। पिछड़ों, दलितों, को उनका हक दिलाना है। सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया जाता है पर समाज में गैरबराबरी है। सामाजिक न्याय से ही लोगों को लाभ मिलेगा।

महापंचायत को प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर श्री अक्षय यादव पूर्व सांसद भी मौजूद

रहे।

श्री अखिलेश यादव ने टुंडला में डॉ सुखेंद्र यादव और श्री ऊदल सिंह यादव के आवास पर जाकर भेंट की। शिकोहाबाद में डॉ दिलीप यादव पूर्व एमएलसी के पिता स्व फूल सिंह तथा जिला मैनपुरी में फौजी शहीद भूमिराज सिंह यादव की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया।





भाजपा को हटाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे समाजवादी

बुलेटिन ब्यूरो

स

माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने आह्वान किया है कि समाजवादियों को पूरी निष्ठा से लोकतंत्र को बचाने में जुटना है। भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा है इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। भाजपा को हर हाल में सत्ता से हटाने का यह ऐतिहासिक मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना है।

श्री यादव ने 2 दिसंबर को समाजवादी

पार्टी के राज्य मुख्यालय पर विधायकों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में उनसे सीधा संवाद करते हुए कहा कि भाजपा साजिश करने के अपने पुराने काम में लग गई है। वह धोखा देकर वोट चाहती है। भाजपा लोकतंत्र को प्रभावित करने के कई तरीकों के जरिए जनादेश को अपमानित करने पर तुली हुई है। हर राज्य सरकार लोक कल्याणकारी काम करती है परन्तु भाजपा अपनी राजनीति के लिए लाभार्थियों को सुविधाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करके लोकतंत्र

की निष्पक्षता को ही नष्ट करने की साजिश करती है।

उन्होंने कहा कि सात वर्षों से भाजपा सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया। समाजवादी सरकार के कामों से भाजपा अपने कामों की तुलना नहीं कर सकती है। उन्होंने आह्वान किया है कि पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए बूथ स्तर पर सघन जनसम्पर्क अभियान में जुट जाएं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी और पीडीए-पिछड़ा,

दलित, अल्पसंख्यक मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ती रही है। जातीय जनगणना होने से ही समाज के हर वर्ग को भागीदारी और उसके अनुरूप अधिकार मिल सकेंगे। भाजपा जातीय जनगणना नहीं कराकर सभी को हक और सम्मान से वंचित कर रही है।

बैठक में सर्वश्री अवधेश प्रसाद, राजेन्द्र चौधरी, (पूर्व मंत्रीगण), प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सांसद जावेद अली, अरविन्द कुमार सिंह पूर्व सांसद, पूर्व सांसद आलोक तिवारी के अलावा सर्वश्री विधायकगण रामअचल राजभर, आलम बदी, कमाल अख्तर, सुधाकर सिंह, मनोज पारस, रामअवतार सैनी, नवाब इकबाल, समरपाल सिंह, प्रभुनारायन यादव, संग्राम सिंह यादव, आर.के. वर्मा, वीरेन्द्र यादव, आशु मलिक, संदीप पटेल, लकी यादव, रफीक अंसारी व एमएलसीगण डॉ मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा अलावा पूर्णमासी देहाती पूर्व विधायक, उदयवीर पूर्व एमएलसी, डॉ राजपाल कश्यप पूर्व एमएलसी, रामबृक्ष सिंह यादव पूर्व एमएलसी, लल्लन यादव पूर्व एमएलसी तथा योगेश प्रताप सिंह पूर्व विधायक आदि उपस्थित रहे।

इधर 16 दिसंबर को पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ के डॉ राममनोहर लोहिया सभागार में एकत्र कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता देश में परिवर्तन करेगी। पीडीए जीतेगा और भाजपा हारेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हरायेगा। भाजपा हटेगी तो देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा।

लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है तभी बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर का संविधान बच सकेगा। संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी और पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध षडयंत्रकारी

रणनीति बनाने में जुटी है।

हमें भाजपा की चालों से सावधान रहना है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सामाजिक सद्भाव को खत्म कर रही है। उसने बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों से सीखी है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी आदत से मजबूर है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए कामों का ही वह उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है तभी बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर का संविधान बच सकेगा। संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। जातीय जनगणना होगी तभी समानुपातिक ढंग से सबको हक और सम्मान मिल सकेगा। लोकतंत्र, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता की तभी गारंटी होगी। बैठक में श्री अनीस मंसूरी के साथ पसमांदा समाज के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस अवसर पर श्री अनीस मंसूरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पसमांदा समाज के लोग श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। श्री अखिलेश यादव ही पिछड़े मुसलमानों के हितैषी है।





सपा को मिल रहा बाकी दलों का साथ

बुलेटिन ब्यूरो

लो

कसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को अन्य दलों का साथ मिलता जा रहा है। ये दल, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और पूरे दमखम के साथ 2024 में साथ मिलकर लड़ने की तैयारी में हैं। पूर्वांचल में भी कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं जिससे

सामाजिक न्याय की श्री अखिलेश यादव की लड़ाई को और धार मिली है। 4 दिसंबर को वारणासी में नेशनल इक्वल पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई। इक्वल पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन श्री अखिलेश यादव से कराकर स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वह श्री अखिलेश यादव के साथ है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय

अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने देश को जो संविधान दिया है उससे हर एक को हक और सम्मान मिला। डॉ भीमराव अम्बेडकर और डॉ राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों और नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। समाजवादी पार्टी सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करती



है। बराबरी की बात करने का मतलब है सबको साथ लेकर चलने की बात हो, सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात करें, वहीं असल में सबका साथ है। सबका साथ तभी जब आप इकल हों।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि असमानता रहेगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब समाज में समानता और सम्पन्नता हो। नेशनल इकल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने समाज को जोड़ने की दिशा में संगठन बनाया है। वह संविधान प्रदत्त अधिकारों को बचाने का काम करेगा। श्री यादव ने

कहा कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम दूसरे होंगे। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। भाजपा जैसी पार्टी से मुकाबला करने के लिए बहुत ही अनुशासन में रहकर उसी की रणनीति से उसी को मात देना है। भाजपा बहुमत कैसे पाती है विश्लेषण करना होगा। हम लोग निराश नहीं हैं, वैसे तो बहुतों की उम्मीदें टूटी हैं पर लड़ाई लंबी है। राजनीति में लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वाले लोग चुनाव में आने वाले हैं। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने जो वादा

किया था वह पूरा हुआ क्या? मसलन क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? नौजवानों को नौकरी, रोजगार मिल गया? मुझे उम्मीद है कि देश का नौजवान यह नारा देगा कि घर-घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार?

श्री यादव ने वाराणसी में आयर बाजार थाना चोलापुर में श्री दिनेश यादव अध्यक्ष बारह दिवसीय बिरहा दंगल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने अपील की कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी आंदोलन में सहयोग करें।

लोकतंत्र का अंतिम क्षण है...!





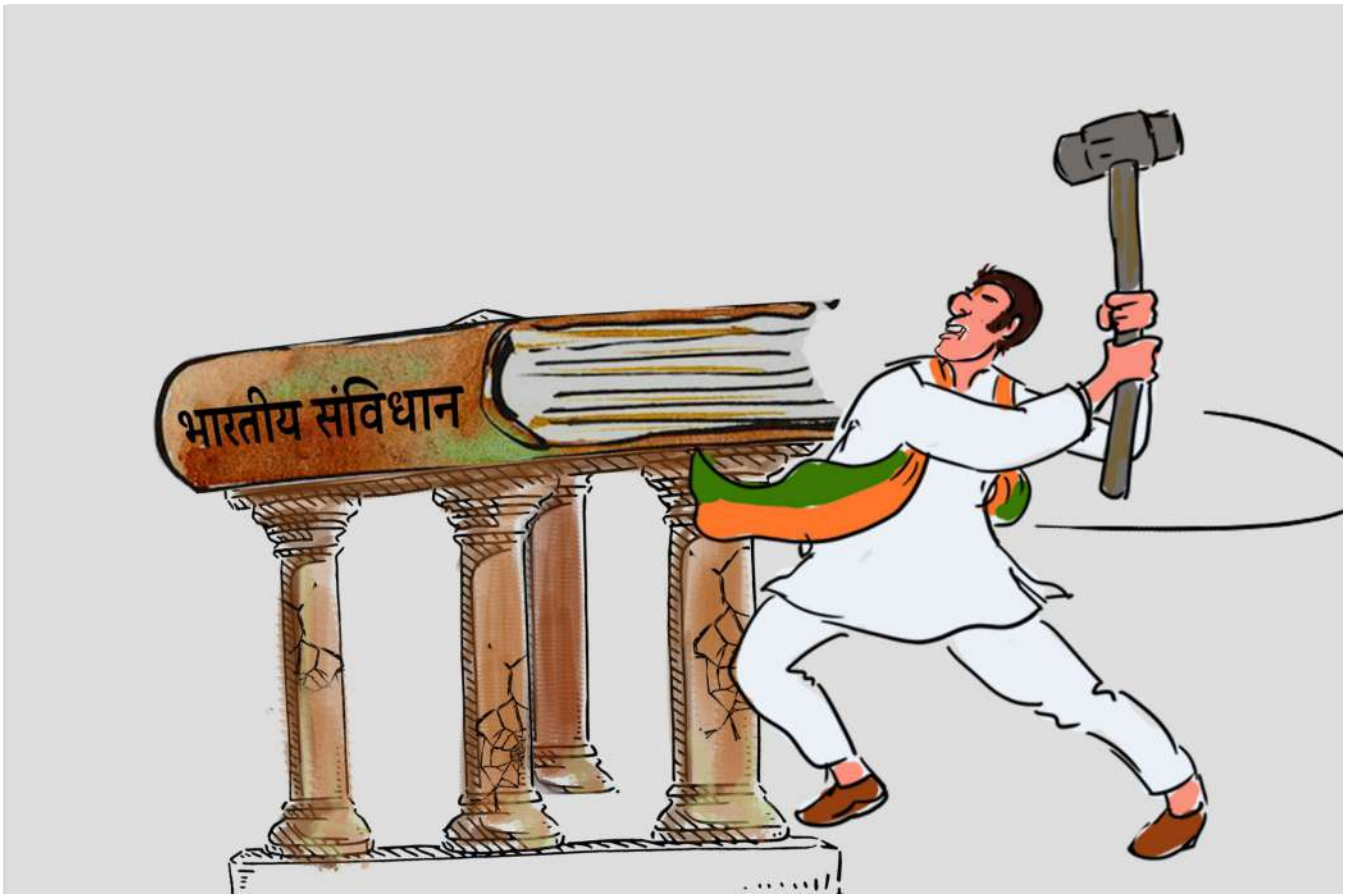
रघुवीर सहाय की कविता आज बोलती हुई संसद के सड़क तक चल रही है:—
लोकतंत्र का अंतिम क्षण है
कह कर आप हंसे
आप सभी हैं भ्रष्टाचारी कह कर
आप हंसे
कितने आप सुरक्षित होंगे
कह कर आप हंसे
चारों ओर बड़ी लाचारी
कह कर आप हंसे.....

सं

सद में संसदीय सुरक्षा पर बहस की मांग करते विपक्ष को जिस तरह से संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया उस कार्रवाई ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि मौजूदा सरकार और उसे चला रहे संगठन लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करने पर आमादा है। कुल 146 सांसदों का निलंबन कोई सामान्य घटना नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद पर हुए हमले से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों पर संसद के बाहर

बयान देते हैं लेकिन संसद के भीतर बयान देने और बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके लिए संसद एक खिलौना है अपनी सत्ता की हनक दिखाने का। तमाम फैसले वे बाहर ही करते हैं और संसद में उन पर सवाल उठने का मौका नहीं देते। आखिर जिन लोगों ने संसद पर हमला किया वे किस बात से दुखी थे और क्या कहना चाहते थे। उस मुद्दे को कैसे हल किया जा सकता है कि बेरोजगार नौजवानों में हिंसा की प्रवृत्ति न पनपे। सुरक्षा में कैसे चूक हुई और

इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह अहम सवाल है लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि इस पर बात नहीं होगी। इसी मामले पर बहस की मांग करने वाले जिन 146 सांसदों को निलंबित किया गया है वे देश की 34 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा से 97 सांसद निलंबित किए गए हैं। वे देश की 15 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि राज्य सभा से निलंबित हुए 46 सांसद 19 करोड़ आबादी की प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो



यह देश की 25 प्रतिशत आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को खामोश कर देना या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा देना लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें डिंपल यादव, जावेद अली खान, कुंवर दानिश अली, रामगोपाल यादव, एसटी हसन शामिल हैं। वे प्रदेश की 1.5 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेताओं ने साफ कहा है कि यह संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास है। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि

संसद परिसर में घुसने वाले युवा संसद में सिर्फ गैस कनस्तर ही नहीं लाए थे वे अपने साथ एक गंभीर मुद्दा भी लेकर आए थे। सत्तापक्ष कह रहा है कि हम तो निलंबित नहीं करना चाहते थे लेकिन विपक्षी सांसदों ने कहा कि हमें बाहर जाना है।

सवाल है कि एक गंभीर मसले पर सत्तापक्ष और विपक्ष मिलजुल कर चर्चा करे यह देश के हित में है या विपक्ष को बाहर करके, उसे बदनाम करके, न्याय, नागरिक और साक्ष्य संबंधी कानून पारित करवा कर सरकार को और अधिकार देना देश के हित में है? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 1860 में जब आईपीसी, सीआरपीसी और

साक्ष्य अधिनियम जैसे कानून ब्रिटिश संसद से पारित करके भारत में लागू किए गए थे तब उनका उद्देश्य भारत में कानून व्यवस्था कायम करने से ज्यादा 1857 में उठे विद्रोह के बचे खुचे अवशेषों का दमन करना था और जनता के भीतर ऐसा भय पैदा करना था कि वह फिर विद्रोह न कर सके। मौजूदा सरकार ने भी इन कानूनों को उससे भी ज्यादा सख्त इसलिए बनाया है कि इस देश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अपनी आवाज न उठा सकें और उठाएं तो उनका दमन किया जा सके।

क्या यही रामराज्य है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस रामराज्य की

कल्पना की थी वह ये तो नहीं था। वहां यूएपीए और राजद्रोह जैसे कानूनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां जनता पर बुलडोजर चलाते रहने का विधान नहीं था।

गांधी ने कहा था कि मेरा रामराज्य दशरथ के पुत्र राम का राज्य नहीं है। मेरा रामराज्य एक ऐसी लोकतांत्रिक कल्पना है जो जनता के दिमाग में एक सुनहरे शासन के रूप में बैठी हुई है। वह तालस्ताय के ईश्वर के राज जैसा है, वह खलीफा से शासन जैसा है जहां पर खलीफा जनता से इकट्ठा किए गए करों में से अपने लिए कुछ नहीं रखता बल्कि सब उसी पर खर्च कर देता है।

वह रैदास के बेगमपुरा जैसा है जहां पर किसी के पास कोई गम नहीं है। उनके लिए रामराज्य का मतलब स्वराज से था लेकिन उस स्वराज में अंग्रेजी सेना के जाने के बाद जनता के दमन के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को अधिकार देने की बात नहीं थी।

न ही ब्रिटिश पूंजीपतियों के जाने के बाद संसाधन और संपदा पर भारतीय पूंजीपतियों के कब्जे का विधान था। वहां तो नागरिकों के अधिकारों की गारंटी थी और पूंजीपति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं ट्रस्टी होता। इसी बात को 1935 में डा राम मनोहर लोहिया ने नागरिक अधिकारों की पुस्तिका लिखकर व्याख्यायित किया था। तब वे कांग्रेस पार्टी में थे और उस पुस्तिका की

भूमिका पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखी थी।

उनका कहना था कि आजादी के लिए नागरिक अधिकार बहुत जरूरी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों की स्थिति का वर्णन करते हुए उसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा था और नए भारत में उसके लिए अहम स्थान नियत किया था।

गांधी ने कहीं कहा था कि सोने चांदी की हथकड़ियां लोहे के हथकड़ियों से ज्यादा खतरनाक हैं। आज एक ओर जनता को गारंटी योजनाओं के तहत कुछ राशन और सम्मान राशि देकर सोने और चांदी की हथकड़ियां पहनाने का जाल रचा जा रहा है

उन अधिकारों में बोलने, लिखने की आजादी, संगठन बनाने और उसके तहत राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां चलाने की आजादी, विरोध करने की आजादी, सरकार के समक्ष धर्म और जाति के भेदभाव के बिना सभी को बराबरी का व्यवहार

पाने की आजादी शामिल थी।

गांधी ने कहीं कहा था कि सोने चांदी की हथकड़ियां लोहे के हथकड़ियों से ज्यादा खतरनाक हैं। आज एक ओर जनता को गारंटी योजनाओं के तहत कुछ राशन और सम्मान राशि देकर सोने और चांदी की हथकड़ियां पहनाने का जाल रचा जा रहा है तो कुछ लोगों पर यूएपीए लगाकर उन्हें लोहे की हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं।

सोने चांदी की हथकड़ियों से बांधने का सबसे ज्यादा प्रभाव राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी कर रहे युवाओं के साथ देखा जा सकता है।

उन्हें नागरिक अधिकारों, लोकतंत्र और विपक्ष की कोई फिक्र नहीं है। वे सरकार के हर दमनकारी कानून और गतिविधि का समर्थन करते हैं।

यही वजह है कि वीडेम नामक संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावी लोकतंत्र की सीढ़ी पर भारत का नंबर 2023 में 108 वां हो गया है जबकि 2022 में यह 100 वें पायदान पर था। इसी तरह रिपोर्टर्स बिदाउट बार्डर्स के सर्वे के अनुसार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कुल 180 देशों में भारत का नंबर 161 वां है।

इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री यह कहते हुए नहीं थकते कि लोकतंत्र हमारे प्राण में बसता है। भारत सरकार ने जी-20 के सम्मेलन के दौरान एक

पुस्तिका प्रकाशित की जिसका शीर्षक था—भारत द मदर आफ डेमोक्रेसी। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लोकतंत्र की जननी का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है।

हमारे यहां हजारों साल से लोकतंत्र की महान परंपरा रही है। हमारी विविधता हमारे लोकतंत्र की महान कसौटी है। यह ऐसा देश है जहां दर्जनों भाषाएं, हजारों बोलियां, विभिन्न जीवन शैलियां और तमाम तरह के भोजन हैं। यह एक जीवंत लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

इस इस पुस्तिका में बुद्ध अशोक, अकबर और भक्ति आंदोलन के संतों समेत लोकतंत्र की बहुत सारी परंपराओं का जिक्र है लेकिन महात्मा गांधी की अहिंसक राजनीति का जिक्र नहीं है। इसमें पंडित नेहरू, डा लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे

लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं।

दरअसल आज भारत पर शासन करने वालों को डबलस्पीक में महारत हासिल है। डा लोहिया जिस कथनी और करनी के अंतर को मिटाने की बात करते थे वह इस दौर में बहुत बड़ी खाई बनकर उभरी है। अगर ऐसा न होता तो प्रधानमंत्री पिछले दस सालों में कम से कम एक प्रेस कांफ्रेंस तो करते।

जी-20 में पत्रकारों को राष्ट्राध्यक्षों से सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। इस बात से अमेरिका और वहां का मीडिया नाराज था। इस दौरान वायर के सिद्धार्थ वर्दराजन ने एम-20 मीडिया फ्रीडम समिट किया जिसमें जी-20 देशों के 17 विदेशी संपादकों ने अपनी बात रखी।

उन्होंने माना कि जी-20 देशों में भी लोकतंत्र की स्थिति गड़बड़ है। यह सही है कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र

और विशेष कर संवैधानिक लोकतंत्र की हालत खराब है। वह नागरिक अधिकारों को कुचलकर बहुसंख्यकवाद की ओर जा रहा है।

पूंजी के अधिपत्य को रोकने के लिए दुनिया में समाजवाद नाम की विचारधारा अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में मौजूद है। भारत में समाजवादी आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डा राम मनोहर लोहिया उसके प्रमुख स्तंभ रहे हैं।

उनके प्रभाव में महात्मा गांधी ने भी पूंजीवाद के विकल्प के तौर पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत चलाया था। कभी उस सिद्धांत का इतना प्रभाव था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे गांधीवादी समाजवाद को अपना सैद्धांतिक आधार बनाया था लेकिन



फोटो स्रोत : गूगल

आज वह पूंजीवाद की प्रचंड पैरोकार है।

समाजवादियों के सामने इस समय दो स्तरों पर गंभीर चुनौती है। एक तो लोकतंत्र को बचाने की और दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक आर्थिक व्यवस्था कायम करने की। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बराबरी लाए। लोकतंत्र और आर्थिक सामाजिक बराबरी का चोली दामन का साथ है।

वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसलिए यह बहस बेकार है कि पहले लोकतंत्र बचाया जाए कि पहले आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाई जाए।

डा अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान हमें एक नागरिक और एक वोट का राजनीतिक बराबरी का हक तो देता है लेकिन देश में जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है, ऐसे में यह अधिकार बेमानी है।

आज हम उस स्थिति में आ पहुंचे हैं जहां नेताओं के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बहस चलाने के बजाय पूंजीपतियों की लूट और आम आदमी के संसाधनों पर हो रहे कब्जे पर चर्चा की जरूरत है। इसका परिमाण बहुत बड़ा है लेकिन चर्चा बहुत अल्प।

तानाशाही के मुकाबले के लिए विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के पास एक

हथियार, जाति आधारित जनगणना हो सकती है। बिहार ने उसकी शुरुआत कर दी है लेकिन सिर्फ इसी से बात बन जाएगी कहा नहीं जा सकता।

भारत बहुत बड़ा देश है और इसके हर

समाजवादियों के सामने इस समय दो स्तरों पर गंभीर चुनौती है। एक तो लोकतंत्र को बचाने की और दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक आर्थिक व्यवस्था कायम करने की

हिस्से की सामाजिक संरचना भिन्न है। डा लोहिया ने साफ कहा है कि जातियां दुनिया के हर देश में रही हैं। लेकिन उनके और वर्गों के बीच एक आदान प्रदान का सिद्धांत काम करता रहा है। जब समाज में विकास होता है तो जातियां वर्गों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब सामाजिक विकास ठहरता है तो वे जातियां के रूप में घनीभूत हो जाती हैं। इसलिए जो भी दल जाति जनगणना

के लिए प्रयासरत हैं उन्हें इससे मिलने वाले आंकड़ों का समता और लोकतंत्र के हित में कैसे प्रयोग करना है इस बारे में लंबी और समझदारी वाली रणनीति बनानी होगी।

फिलहाल लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई इस समय सबसे कठिन दौर में है। जनता की चेतना का स्तर बहुत उत्साहजनक नहीं है। विपक्ष को उस चेतना को जगाने के लिए एकजुट रहते हुए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिलहाल इंडिया गठबंधन की बढ़ती एकता से बड़ी उम्मीद है। ■■



उत्तर से दक्षिण तक जातीय जनगणना की गूंज

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को सही अनुपात में उन्हें हक दिलाने के लिए जातीय जनगणना की मांग को जोरदार तरीके से उठाकर पूरे देश में इस मांग को लेकर ऐसा माहौल बना दिया कि अब उत्तर से दक्षिण तक पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने की आवाज उठ रही है। बीते दिनों चेन्नई में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा अनावरण के

कार्यक्रम में मंडल कमीशन के हवाले से फिर इस मांग ने जोर पकड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव खास मेहमान थे। उन्होंने समारोह में मंडल कमीशन के हवाले से एक बार फिर जातीय जनगणना कराए जाने की जोरदार वकालत की। श्री अखिलेश यादव ने तर्क दिया कि मंडल कमीशन के बाद अब जातीय जनगणना के लिए लड़ाई लड़नी है ताकि शोषितों, वंचितों को उनका अधिकार मिल सके।

27 नवंबर को चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में समारोह को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चेन्नई में प्रतिष्ठित प्रेसीडेंसी कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा लगना दक्षिण भारत के साथ-साथ पूरे देश खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा के लिए बड़ा संदेश है। यह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा संदेश है।

श्री यादव ने कहा कि श्री वी.पी. सिंह ने मंडल

कमीशन की रिपोर्ट लागू करके पिछड़ों को अधिकार और सम्मान दिलाने का काम किया था। जो मंडल कमीशन राजनीतिक दलों को दिख नहीं रहा था, उसे श्री वीपी सिंह ने लागू करने का काम किया था। तब, उनका साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन के पिताजी श्री एम.करुणानिधि, उत्तर प्रदेश से नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव, बिहार से श्री लालू प्रसाद यादव और श्री शरद यादव सहित तमाम नेताओं ने दिया जो दलितों, पिछड़ों की आवाज थे। जिस तरह से बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने दलित आबादी को आरक्षण दिया उसी तरह से मंडल कमीशन लागू होने से पिछड़े वर्गों के सपने पूरे हुए।

उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश में वी.पी. सिंह और उनके साथ के नेताओं को तमाम तरह का विरोध झेलना पड़ा था और बातें सुननी पड़ी थी। मंडल कमीशन के विरोध में आंदोलन हुआ। बसें जला दी गईं। सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई। उस समय जिन लोगों ने पिछड़ों के अधिकारों का विरोध किया था। जान देने का प्रयास किया था, न जाने क्या- क्या बातें कहीं थी वहीं लोग 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने में सबसे आगे रहे। हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि पिछड़ों को किस तरह से हजारों सालों से अधिकार से वंचित रखा गया था जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला था।

श्री यादव ने कहा कि दिल्ली की सरकारों ने पिछड़ों को अधिकार नहीं दिया। दिल्ली की सरकारें निजीकरण की तरफ जा रही हैं। अगर सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा तो संविधान के अनुसार हक और सम्मान



कैसे मिलेगा। पिछड़ों को जो हक दिलाया गया है वह सपना कैसे पूरा होगा? जो रास्ता डॉ राममनोहर लोहिया, नेताजी ने देखा था उसे पूरा करना है। उन सभी नेताओं के संघर्ष को याद करना हम सबका दायित्व है जिन्होंने जोखिम उठाकर पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देकर उन्हें हक और सम्मान दिया और पिछड़ों, दलितों के आरक्षण को बढ़ाया।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बात यही नहीं खत्म होती है। अब जातीय जनगणना का मामला है। जातीय जनगणना के साथ कैसे लोगों को बराबरी पर खड़ा किया जाए। जातीय जनगणना होने से सभी जातियों की संख्या की जानकारी होगी। उन्हें हक और सम्मान दिलाया जा सकेगा। जातीय जनगणना से ही सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा होगा।

श्री यादव ने मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन को भरोसा दिलाया कि आप जिस विरासत

को आगे बढ़ा रहे हैं उससे हजारों सालों से अधिकारों से वंचित लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है। वे लोग हमारे साथ खड़े होकर साथ देंगे। श्री वी.पी. सिंह की प्रतिमा लगाने का फैसला करके नई ऊर्जा देने और नई रोशनी दिखाने का काम किया गया है। यह आने वाली पीढ़ी को हिम्मत देने का काम करेगा। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जो रास्ता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, डॉ राममनोहर लोहिया और दक्षिण भारत में श्री एम. करुणानिधि ने दिखाया है। उस पर आगे चलकर दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को हक और सम्मान दिलाना है।

कार्यक्रम को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर श्री वी.पी. सिंह की पत्नी श्रीमती सीता कुमारी और उनके पुत्र श्री अजय सिंह आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।





भाजपा राज में किसान बेहाल : अखिलेश

बुलेटिन ब्यूरो

बे

वर (मैनपुरी) के घुटारा गांव में 23 नवंबर को आयोजित एक सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुनियादी समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, गरीबों के इलाज से भाजपा का कोई मतलब नहीं है। लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। सड़कों पर सांड घूम रहे हैं। किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान बेहाल हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता चाहे जिस हालात में रहे भाजपा के लोगों को कोई फिक्र नहीं है। भाजपा ने जनता से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। किसानों को कोई

सुविधा नहीं मिल रही है। किसान संकट में हैं। छुट्टा जानवर किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। छुट्टा जानवर लोगों की जान ले रहे हैं। प्रदेश में हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है। हजारों करोड़ खर्च हो गए लेकिन यह सरकार छुट्टा जानवरों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिली। इस सरकार ने प्राइवेट कम्पनियों से खरीदवा दिया। खेतों में सरसों है। सरकार विदेशों से तेल आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार आने पर सरकारी एजेंसी से ही किसानों के गेहूं की

खरीद करेंगे। मंडी के माध्यम से किसानों को अच्छा भाव देंगे। इस सरकार में प्राइवेट कम्पनियों ने आढ़तियों के माध्यम से खरीद लिया। बिचौलियों और कम्पनियों ने मुनाफा कमाया। किसानों को कीमत नहीं मिली।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी से नेताजी का बहुत पुराना और अटूट संबंध रहा है। यहां बहुत वरिष्ठ लोग ऐसे हैं जोकि हर परिस्थिति में नेताजी के साथ रहे, संघर्ष किया। वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद नौजवानों का साथ मिल गया तो समाजवादी पार्टी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। राजनीति में जिनकी कोई आवाज नहीं थी नेताजी उनकी आवाज बने और उन्हें पहचान दिलाने का काम किया। गरीबों, किसानों को सम्मान दिलाने

का काम किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगुना करने का वादा किया था लेकिन उसका वादा झूठ और हवाई साबित हुआ। भाजपा की केन्द्र और प्रदेश की सरकार अब किसानों की बात भी नहीं करती है। किसानों का धान नहीं खरीदा गया। गन्ना किसान तो पूरी तरह भगवान भरोसे है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों को धोखा दिया है। पिछले दो सालों से गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। गन्ने की खेती की लागत बढ़ रही है। गन्ना किसानों को नुकसान हो रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ताकत में आने पर अग्निवीर योजना समाप्त कर फौज में पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। अग्निवीर योजना में नौजवानों को सम्मान नहीं मिल रहा है। रिटायर होने के बाद कोई सुविधा नहीं है। अग्निवीर योजना खत्म कराना और सेना की पक्की नौकरी की व्यवस्था कराना जरूरी है क्योंकि सीमा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग झूठे हैं। इनसे जनता बचकर रहे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएगी। जो दल भाजपा को हराना चाहते हैं वे समाजवादी पार्टी का साथ दें। उनकी रणनीति भाजपा के मुकाबले के लिए बननी चाहिए। हम भाजपा को हराना चाहते हैं। ■■

किसानों के मसीहा को श्रद्धासुमन अर्पित



बुलेटिन ब्यूरो

पू

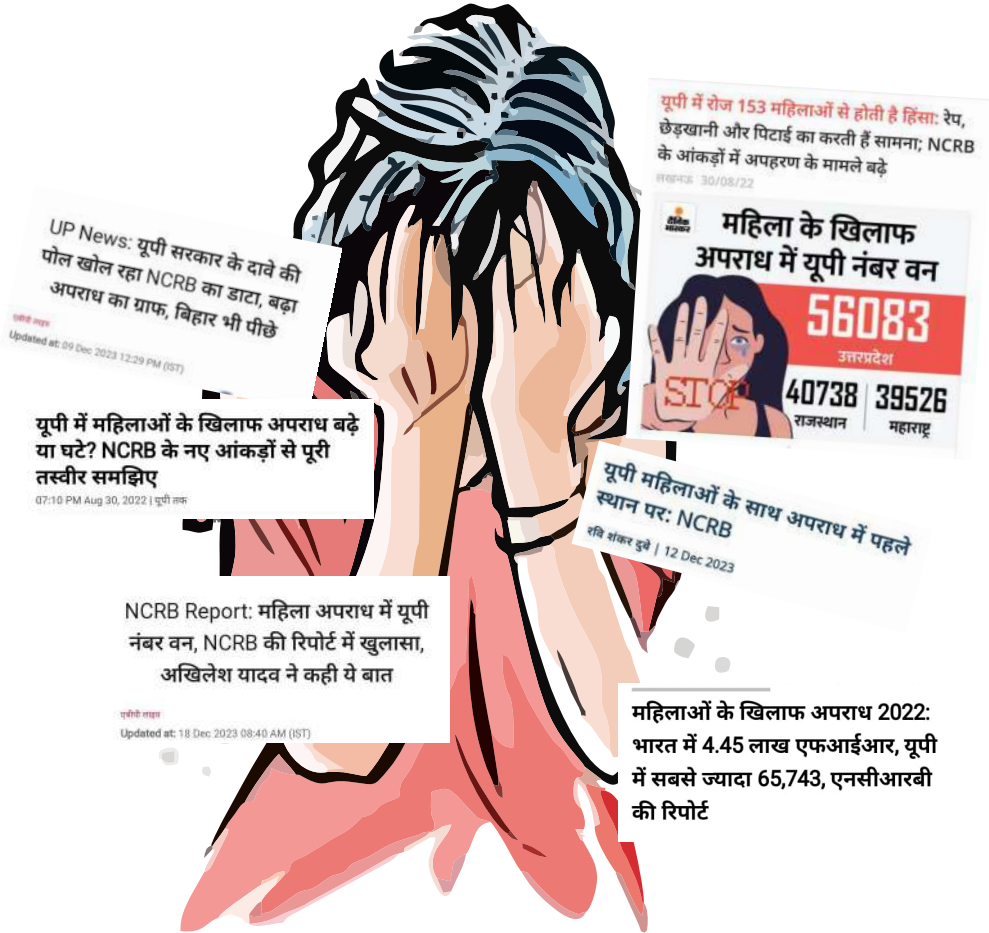
र्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती किसान दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर सादगी से मनाई गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी की आर्थिक नीतियों के चलते ही देश के किसानों के प्रति न्याय का रास्ता प्रशस्त हुआ है। समाजवादी पार्टी उनके रास्ते पर चलते हुए किसानों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है।

श्री अखिलेश यादव ने चौधरी साहब को नमन करते हुए कहा कि उनके बताए हुए रास्ते से ही गांवों का विकास तथा किसानों की तरक्की होगी। चौधरी साहब का मानना था कि जब तक देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को खुशहाल किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। चौधरी साहब भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता थे।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने पर आमादा है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सभी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। भाजपा सरकार चौधरी साहब के नाम के सहारे किसानों को भ्रमित करने के लिए तरह-तरह के आयोजनों का नाटक कर रही है। ■■

यूपी में आधी आबादी सर्वाधिक असुरक्षित



बुलेटिन ब्यूरो

कें

द्र सरकार के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी NCRB ने यूपी की भाजपा सरकार की पोल खोल दी है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक यूपी, देश का वह सूबा है जहां सर्वाधिक अपराध हुए हैं और यूपी महिला अपराध में भी नम्बर वन पर है। यह आंकड़े साबित करते हैं कि यूपी में अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का राज्य

सरकार और केंद्र के भाजपा नेताओं का दावा कितना हवा हवाई है। NCRB ने 3 दिसंबर को क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 शीर्षक से देश में हुए अपराधों का वार्षिक विवरण जारी किया है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, बलात्कार के बाद हत्या, गैंगरेप व महिलाओं के खिलाफ होने वाले दूसरे अपराधों में यूपी नंबर वन है। NCRB के अनुसार वर्ष 2022 में उत्तर

प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65743 मामले दर्ज हुए जोकि किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक हैं। इतना ही नहीं साल दर साल आंकड़ों में इजाफा भी हुआ है यानी महिलाओं पर अपराध रुकने के बजाए उसमें बढ़ोत्तरी ही दर्ज की गई है। आंकड़ें बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा यूपी में ही दर्ज हुए। यहां 2020 में 49385 मामले दर्ज हुए। मामलों में कमी के बजाए 2021

अपराध नियंत्रण का दावा सिर्फ जुमला

बुलेटिन ब्यूरो

स

माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध थम नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपराध नियंत्रण का दावा अब जुमला भर रह गया। जनता आतंक तथा भय के माहौल में जीने को विवश है। जीरो टॉलरेंस अब जीरो हो गया है। उन्होंने चिंता जताई कि अब यूपी में महिलाओं, बच्चियों के अलावा बच्चे भी यौन उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। यह शासन और प्रशासन के लिए शर्म की बात है।

उन्होंने कहा है कि राजधानी लखनऊ में ही महिलाएं-बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मुख्यमंत्री का रोमियो स्क्वाड और गश्ती पुलिस दल वारदातों के समय कहीं दिखाई नहीं देता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अधिकारी की बेटी के साथ लखनऊ से बाराबंकी के 20 किलोमीटर रास्ते में दुष्कर्म की कलंकपूर्ण घटना हुई।

उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हद तो यह है कि अब अधिकारी स्तर की महिलाएं भी अपनी आबरू नहीं बचा पा रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए के स्टेनो पर परेशान करने की शिकायत की है। उन्होंने इस रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर चार दिन में एक बच्चा यौन शोषण का शिकार हो रहा है।

आंकड़ों से यह सच्चाई स्पष्ट है और अपराध की ये घटनाएं विचलित करने वाली हैं। वाराणसी में वर्ष 2022 में 18 साल से कम उम्र के 46 बच्चे-बच्चियां दुष्कर्म की शिकार हुईं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में 485 महिलाओं ने अपने उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज कराए। दहेज हत्या के 25 केस दर्ज हुए। 208 महिलाओं का अपहरण हुआ।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा सरकार के पास सिर्फ जुमले हैं और बहकाने के लिए झूठे आश्वासन हैं। भाजपा ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन जैसी योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए शुरू की हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और नारी वंदन उनके क्रंदन से अभिशापित है। ■■



में इसमें और इजाफा हो गया और यह 56083 तक पहुंच गया। 2022 में आंकड़ों में और उछाल दर्ज किया गया और इसमें 10 हजार से ज्यादा और मामले जुड़ गए और इस तरह 2022 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ 65743 अपराध हुए। NCRB ने जांच की रफ्तार भी सुस्त पाई। 2021 में यूपी में 11732 मामलों की जांच भी अधर में लटकी रही।

NCRB की रिपोर्ट बता रही है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ 13097 मामले सही पाए गए लेकिन अभियोजन उसमें सबूत एकत्र करने में नाकाम रहा। 66936 मामलों को पुलिस ने निस्तारित कर दिया मगर 10539 मामलों की साल के अंत तक जांच भी पूरी नहीं कर सका। NCRB के मुताबिक दहेज हत्या के भी सर्वाधिक मामले यूपी में दर्ज हुए हैं। पति व रिश्तेदारों के जुल्म की शिकार भी सर्वाधिक यूपी की महिलाएं हुई हैं। इस मामले में भी यूपी नम्बर वन पर है और यहां 20371 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं का सर्वाधिक अपहरण भी यूपी में हुआ है। यहां 14887 महिलाओं का अपहरण हुआ। महिलाओं की हत्या में भी देश के सभी राज्यों के मुकाबले यूपी में सर्वाधिक महिलाओं की हत्या हुई। यहां 3491 महिलाओं की हत्या की गई।

NCRB के आंकड़ों के अनुसार यूपी में क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी में देश के अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा अपराध दर्ज किया गया है। अपराधों में पिछले तीन सालों में वृद्धि रिकार्ड की गई है। 2020 में यूपी में 657925, 2021 में 608082 जबकि 2022 में 753675 क्राइम हुआ। यह देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। ■■

जान बचाने वालों का सपा ने मान बढ़ाया



राजेन्द्र चौधरी



उत्तराखंड की सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकाल कर उनकी जान बचाने वाले रैट होल माइनिंग टीम के सदस्यों का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अभिनंदन-सम्मान कर उनका मान बढ़ाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने 8 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर आयोजित एक अभिनंदन समारोह में टीम के सदस्यों को अंगवस्त्र पहनाने के बाद सभी

सदस्यों को 1-1 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि रैट होल माइनिंग टीम के साथियों की राय है कि वे अकेले दम यह बड़ा काम नहीं कर सकते थे। सबने मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि टीम के साथियों के मंतव्य को पूरे देश को समझना चाहिए कि मिलकर काम करने से ही कामयाबी मिलती है।

अभिनंदन समारोह में श्री अखिलेश यादव ने सर्वश्री अंकुर कुमार, मोनू कुमार, नसीम, मो

इरशाद, वकील हसन, जहूर हसन, फिरोज कुरैशी, मो रशीद, नसरुद्दीन, इरशाद, जतिन कश्यप, सौरभ कश्यप, मुन्ना और देवेन्द्र को बधाई देते हुए कहा कि जान बचाने की कोई कीमत नहीं होती है। जान बचाने वाले अनमोल होते हैं। इन साथियों ने अपनी जान की परवाह न कर दूसरों की जान बचाई। सरकार ने जहां सुरंग में फंसे श्रमिकों की मदद की, वहीं इन बचाने वालों की भी मदद करनी चाहिए।

बचाव दल के लीडर श्री वकील हसन और

उनके सहयोगी मुन्ना ने इस अवसर पर कहा कि हमें जहां सुरंग में फंसे साथियों को बचाने पर खुशी हुई थी उससे ज्यादा खुशी अखिलेश जी से मिलकर हुई है। हम सबने मिलकर काम किया। हमारी टीम में हिन्दू मुसलमान दोनों थे। श्री मुन्ना ने कहा कि अखिलेश जी से हुई मुलाकात हमारी दौलत है।

जान बचाने वाले दल का समाजवादी पार्टी द्वारा अभिनंदन करने की चर्चा उत्तराखंड में जोर-शोर से हो रही है। लोग बाग प्रशंसा कर रहे हैं कि उत्तरकाशी की विपदा पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए रैट माइन्स के काम की सराहना की।

उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक सरोकार से कभी भी पीछे नहीं हटी है। पहले भी विपदा में समाजवादी पार्टी ने मदद की है। 24 फरवरी 2021 को समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की ओर से उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से मची भीषण तबाही में 25 लोगों की जान बचाने के लिए श्रीमती मंगसिरी देवी को सम्मानित करते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें 5 लाख रुपये का चेक भेंट किया गया था। तब, श्रीमती मंगसिरी देवी को चेक उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सत्यनारायण सचान, उपाध्यक्ष श्रीमती आभा बड़धवाल द्वारा भेंट किया गया। इस अवसर पर श्रीमती मंगसिरी देवी का बेटा विजेन्द्र कैरिनी भी उनके साथ था। श्री मंगसिरी देवी ने इस सम्मान से अभिभूत होकर कहा था कि हमारा परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभारी है कि उन्होंने उत्तराखंड में हमारा सम्मान बढ़ाया और हमारी मदद की।



फाइल फोटो

इसी तरह 2013 में जब केदारनाथ में भयंकर आपदा में हजारों मौतें हुई थीं और तमाम लोग वहां फंस गए थे तब श्री अखिलेश यादव ने, जोकि उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे, ने 16 जुलाई 2013 को 200 बसों का बेड़ा तैनात किया था ताकि ऋषिकेश और देहरादून में फंसे लोगों को निकाला जा सके। तत्कालीन एडीएम सहारनपुर के साथ डॉ सचान को भी यहां राहत कार्य की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने तब उत्तराखंड सरकार को 25 करोड़ रुपये की मदद भी की थी।

वस्तुतः उत्तराखंड में विकास के प्रति श्री अखिलेश यादव चिंतित रहते हैं। उनका मानना है कि उत्तराखंड में कोई भी परियोजना पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के अध्ययन के बाद ही लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे संवेदनशील और नए हैं। ऋषिकेश, कर्ण प्रयाग के बीच बन रही रेल लाइन के प्रति भी तमाम आशंकाएं हैं।

उत्तराखंड की सुरंग में श्रमिकों के फंसने की घटना के हवाले से श्री अखिलेश यादव ने

उत्तराखंड में पर्यावरण की अनदेखी कर विकास के नाम पर विनाशपरक योजनाएं चलाने का विरोध करते हुए कहा है कि सुरंग निर्माण में जो अनियमितता बरती गई उससे 41 श्रमिकों की जिंदगी दांव पर लग गई थी। यहां मानव श्रम के साथ लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

(लेखक पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं)



तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश से समर्थन मांगा



बुलेटिन ब्यूरो

नि

र्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेंपो सोनम तेनफल

ने विधान भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताने तथा स्वतंत्र तिब्बत के लिए आवाज उठाने का आग्रह किया।

बाद में तिब्बती सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचकर श्री अखिलेश यादव से अलग से भेंटकर तिब्बत के मौजूदा हालात और चीन द्वारा उसकी स्वतंत्रता हड़पे जाने के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की।

28 नवंबर को विधान भवन में विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना, पूर्व स्पीकर माता

प्रसाद पाण्डेय, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी एवं श्री मनोज पाण्डेय की उपस्थिति में श्री खेंपो ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से भेंटकर एक ज्ञापन देते हुए कहा कि तिब्बत अब अपने सांस्कृतिक संहार और पहचान के पूर्ण विनाश के खतरे का सामना कर रहा है।

श्री खेंपो ने श्री अखिलेश यादव को दिए गए ज्ञापन में कहा कि 1949 में तिब्बत पर चीन द्वारा आक्रमण के बाद से तिब्बती लोगों के मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तिब्बत के भीतर 60 लाख से अधिक तिब्बतियों के प्रति चीन के दमनात्मक रवैये के खिलाफ पिछले 74 वर्षों से शांतिपूर्ण प्रतिरोध जारी है और लोग बेबसी में चीनी औपनिवेशिक कब्जे को सहन कर रहे हैं।

तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन और अनुचित उत्पीड़न हो रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियां चला रहा है।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करने के लिए बिना किसी पूर्व शर्त के परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ ठोस बातचीत में फिर से शामिल होने की व्यवस्था हो।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों तथा तिब्बत की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ राममनोहर लोहिया तथा नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने तिब्बत की आजादी के लिए आवाज उठाई थी। उनका



स्पष्ट मत था कि भारत को पाकिस्तान के मुकाबले चीन से ज्यादा खतरा है। समाजवादी पार्टी तिब्बत की स्वतंत्रता को भारत की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक मानती है। चीन में भारत के मानसरोवर जैसे तीर्थ हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की स्पष्ट नीति से प्रभावित होकर उनसे पुनः भेंट करने के लिए 30 नवंबर को निर्वासित तिब्बती संसद के सांसदों का एक प्रतिनिधिमण्डल समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमण्डल में सर्वश्री लोपेन थुपटेन ग्यात्सेन, बांगडू डोरजी तथा सुश्री पेमा चो ने समाजवादी पार्टी के समर्थक रुख के लिए आभार जताया। श्री अखिलेश यादव ने उनका धन्यवाद जताया।



परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को नमन

बुलेटिन ब्यूरो

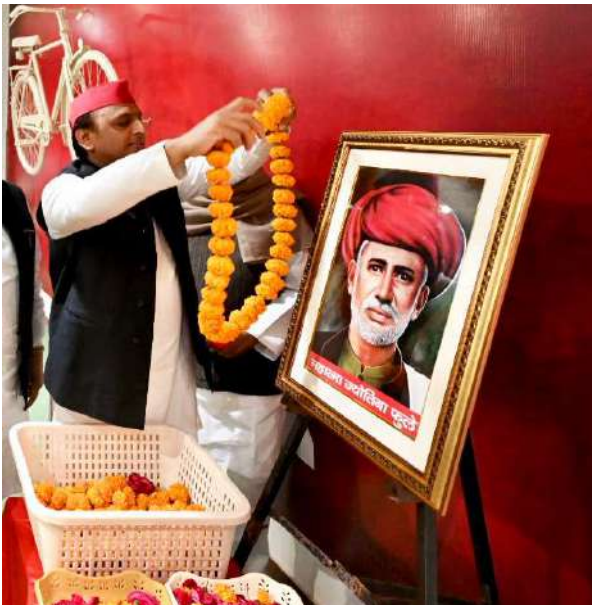
समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय समेत प्रदेश के सभी जिलों में सपा कार्यालयों पर 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके बताये रास्ते पर चलते हुए संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी स्मृति को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहब को भारतीय संविधान के निर्माता एवं महान समाज सुधारक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग सड़क से सदन तक उठा रही है ताकि समाज में हर जाति को समानुपातिक भागीदारी तय हो सके।



समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं ज्योतिबा फुले

बुलेटिन ब्यूरो



समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर 28 नवंबर को समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने की। बैठक में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने उनके कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

महात्मा फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा फुले ने नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के आह्वान के साथ दलित समाज के साथ रहे भेदभाव की निंदा की और महिलाओं की शिक्षा के साथ उनके अधिकारों की भी लड़ाई लड़ी।

सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित

बुलेटिन ब्यूरो

स

माजवादी पार्टी
मुख्यालय, लखनऊ में
15 दिसंबर को

लौहपुरुष सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर कहा कि भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद भारत में स्वतंत्र रियासतों को भारत संघ में विलय



कराने में अभूतपूर्व योगदान रहा है। भारत को अखंड और सशक्त बनाने का महान कार्य उन्होंने नहीं किया होता तो हम

स्वतंत्रता का पूरा अर्थ खो देते। सरदार पटेल ने जीवन का हर क्षण भारत में एक राष्ट्र का भाव जागृत करने में समर्पित किया।

सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे संत गाडगे

बुलेटिन ब्यूरो

म

हान संत गाडगे महाराज
की पुण्यतिथि 20
दिसंबर को समाजवादी

पार्टी कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनायी गयी। पूर्व नेता विरोधी दल रामगोविन्द चौधरी ने संत गाडगे के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया।

संत गाडगे की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि महान संत गाडगे महाराज



सामाजिक क्रांति के अग्रदूत एवं स्वच्छता अभियान के जनक थे। उन्होंने सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कार्य किया। उन्होंने

जीवन पर्यन्त गरीबों, अनाथों, विकलांगों की सेवा की।



Following

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

ये उग्र में अपराध के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के ज़ीरो हो जाने का परिणाम है। निंदनीय!

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

तोड़कर हर बंदिश को कोई जब सर पर रख देता है हाथ उनकी जंग लड़ने की खातिर तब खुद पर बढ़ता है ऐतबार जिससे बढ़ता है वो हौसला जो लाता है अंदर इंकलाब!

जनता का ये विश्वास और आशीर्वाद ही संघर्ष की शक्ति को बढ़ाता है, बदलाव की नयी मशाल जलाता है।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

@Noida



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी एवं अन्य सभी नेतागणों की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल कार्यालय के उद्घाटन के दौरान।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

इटवा लॉयन सफ़ारी में 4 महीने में 14 वन्य जीवों की मौत की असली वजह प्रशासन की लापरवाही और प्रबंधन की संवेदनहीनता है। पर्यावरण-चक्र में हर जीव का अपना महत्व होता है। सपा, भाजपा सरकार से माँग करती है कि इसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ सख्त-से-सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

हुक्मरान की तरफ नज़र उठाने की पाबंदी है शहर में खिलाफ़त के खिलाफ़ नज़रबंदी है!

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

अब जब ये समाचार है कि उग्र 'महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों' में नंबर वन पर है तो भाजपा सरकार ये कुतर्क देगी कि जब उग्र की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो अपराध भी सबसे ज़्यादा होंगे; तो ऐसे में जनता ये कहेगी कि अगर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो संसाधन भी तो सबसे ज़्यादा हैं। भाजपा ऐसी बचकानी दलीलों से महिलाओं के खिलाफ़ हो रहे अपराधों के सत्य और तथ्य को दबा नहीं सकती।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

वाह स्मार्ट सिटी वाह....



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

PDA ही NDA को हरायेगा

PDA सामाजिक आंदोलन है... सामाजिक न्याय का संघर्ष है।



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

कुछ लोग आइने में देखकर पढ़ते हैं खुद पर शायरी हर बार, जिसमें होती है उन्हीं की बात, उन्हीं का किरदार।

प्रिय प्रदेशवासियों,

उप्र भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज़ पर बेची जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों-करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं, तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक रही है कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे।

अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाएं।

सरकार ऐसे फ़ैसलों से घर-परिवार को बर्बाद न करे। महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फ़ैसले के विरोध में उप्र की महिलाएँ, परिवारवाले और युवा, भाजपा को हटाने का फ़ैसला करेंगे।

शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। ये भाजपा राज में अपराध के खिलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस के ज़ीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा।

अखिलेश यादव

अखिलेश यादव

राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी

